सं0-21/2018/1260/62-2-2018-2/3(19)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई सम्बन्धित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन जिला योजना के अन्तर्गत मध्यम गहरे नलकूप योजना में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-2364/ल0सिं0/बजट-SCSP/TSP/2018-19, दिनांक 12.03.2018 व पत्र संख्या-2544/ल0सिं0/बजट-SCSP/TSP/2018-19, दिनांक 28.03.2018 एवं पत्र संख्या-जी-208/ल0सिं0/बजट-3/2018-19, दिनांक 03.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस/2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत योजना में एस0सी0एस0पी0 के कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-870.57 लाख (रू0- आठ करोड़ सत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत मध्यम गहरे नलकूप की योजना पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड़ जो किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-3941/62-2-2012-2/2 (10)/2012, दिनांक 20-11-2012 द्वारा निर्गत गार्डड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत योजना मे प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियॉ संशोधित कर ली जायेंगी।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2018 तक
3-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण्	15-12-2018 तक
4-	वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2019 तक
5-	आवंटन का समर्पण	15-03-2019 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-एलूबियम क्षेत्रों में मध्यम गहराई के नलकूपों का निर्माण-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:- यथोक्त।</u>

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2018/1260(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्र्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।

7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।

8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

14- एन0आई0सी0 की प्रति।

15- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

शासनादेश सं0-21/2018/1260/62-2-2018-2/3(19)/2018, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-एलूवियम क्षेत्रो में मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	गत वर्ष 2017-18 में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	अतिरिक्त परिव्यय	कुल परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रस्तावित अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मुजफफनगर	6.00		6.00	3.06	3.06
2	मथुरा	30.60		30.60	18.36	18.36
3	मैनपुरी	22.95		22.95	13.77	13.77
4	अलीगढ़	90.00		90.00	52.02	52.02
5	बरेली	45.90		45.90	26.01	26.01
6	बदायूँ	3.06	1.53	4.59	4.59	4.59
7	शाहजहॉपुर	7.65		7.65	6.12	6.12
8	मुरादाबाद	7.65		7.65	6.12	6.12
9	रामपुर	3.06		3.06	1.53	1.53
10	बिजनौर	0.00	6.12	6.12	6.12	6.12
11	सम्भ्ल	0.00	1.53	1.53	1.53	1.53
12	लखनऊ	22.95		22.95	13.77	13.77
13	हरदोई	15.30		15.30	9.18	9.18
14	सीतापुर	76.50		76.50	44.37	44.37
15	खीरी	76.50		76.50	3.06	3.06
16	रायबरेली	200.00		200.00	110.16	110.16
17	उन्नाव	45.90	9.18	55.08	55.08	55.08
18	कानपुर नगर	22.95	44.37	67.32	67.32	67.32
19	कानपुर देहात	15.30		15.30	9.18	9.18
20	इटावा	30.60		30.60	18.36	18.36
21	औरैया	129.89		129.89	71.91	71.91
22	फर्रूखाबाद	45.90		45.90	26.01	26.01
23	कन्नौज	99.45		99.45	58.14	58.14
24	इलाहाबाद	122.60		122.60	67.32	67.32
25	कौशाम्बी	45.90		45.90	26.01	26.01
26	फतेहपुर	22.95		22.95	18.36	18.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	प्रतापगढ़	70.00		70.00	4.59	4.59
28	संत रविदास नगर	0.00	15.30	15.30	15.30	15.30
29	अमेठी	53.55		53.55	38.25	38.25
30	झांसी	112.61		112.61	29.07	29.07
31	जालौन	38.25		38.25	24.48	24.48
32	बांदा	38.25		38.25	21.42	21.42
	योग-	1502.22	78.03	1580.25	870.57	870.57

(रूपया आठ करोड़ सत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**